घट-बढ़ के समायोजन संबंधी मामले बकाया पड़े हुए हैं।

(ग) मार्च, 1988 से इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है ताकि बकाया पड़े मामलों को शीघ्र निपटाया जा सके।

(घ) बकाया पड़े मामलों में अदायगियां समय पर करने का सरकार हर संभव प्रयास करेगी।

Free Medical Aid to SC/ST in Rajasthan

*169. SHRI SANTOSH BAGRODIA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government have implemented any comprehensive scheme of free medical aid to SC/ST and backward classes in Rajasthan;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the number of SC/ST and backward classes covered by such schemes in Rajasthan particularly in Bhilwara district till the end of June, 1988?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (KUMARI SAROJ KHAPARDE): (a) to (c) Free medical aid is available at PHCs and sub-centres set up in States to all including SC/STs and backward classes. Furthermore, in areas of concentration of STs and hilly areas Government have relaxed the infrastructure norms and fixed at 20,000 and 3,000 population instead of 30,000 and 5,000 respectively.

वेतरणी नदी पर बांध का निर्माण

*170. श्री राम जेठ मलानी :
श्री राम नरेश यादव :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा के जनजातीय क्षेत्रों में 9570 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु राज्य की वैतरणी नदी पर एक बांध के निर्माण की परियोजना पिछले एक दशक से लंबित पड़ी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं ;

(ग) सरकार द्वारा इस परियोजना को अब तक अनुमोदित न किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार इस परियोजना के निर्माण-कार्य को तेज करने के लिए कदम उठाने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में भावी योजनाएं क्या हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ङ) वेतरणी नदी पर कोई परियोजना, जिससे उड़ीसा के जनजातीय क्षेत्रों मे लगभग 9570 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी, केन्द्र में लंबित नहीं है।

Memorandum of understanding signed with Switzerland for exchange of Economic Information

*171. SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE:
SHRI KAILASH PATI MISHRA:

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) when was the Memorandum of Understanding between India and Switzerland signed for exchange of economic information;

(b) the steps taken so far to approach the Swiss and the Swedish Courts under the International Assistance in Criminal Matters Act, asking for information regarding the beneficiaries of the Swiss Bank accounts into which money was transferred by the Bofors; and

(c) what is the response from the Swiss Banks?